दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || email :- nyaysakshi@gmail.com || रायगढ़, मंगलवार 25 दिसम्बर 2018 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-86

महत्वपूर्ण एवं खास

लंदन के बराबर हुआ राजधानी का तापमान, और गिरने की आशंका

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का तापमान लगातार गिर रहा है. आज सुबह दिल्ली का तापमान लंदन के बराबर पहुंच गया. जहां लंदन का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा वहीं दिल्ली का तापमान भी गिरकर 7 पर पहुंच गया. हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि तापमान अभी और गिरेगा. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच तापमान घटकर 4 डिग्री सेल्सियस या उस से भी कम हो सकता है. लिहाजा दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड और बढ़ सकती है और सर्द हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर निकलते समय ध्यान रखने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है.

माकपा नेता निरुपम सेन का निधन

कोलकाता (आरएनएस)। मार्क्सवादी नेता और वाम मोर्चा सरकार के दौरान महत्वपूर्ण उद्योग विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके पूर्व मंत्री निरुपम सेन का सोमवार सुबह कोलकाता में निधन हो गया. उन्होंने 72 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. सेन पूर्व पोलित ब्यूरो के सदस्य भी रहे हैं. वह पिछले दो साल से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे. सेन को वर्ष 2013 में ब्रेन अटैक हुआ था, जिसके बाद वह मल्टी ऑर्गन फेलियर से गुजर रहे थे. उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. सेन ने वर्ष 2001 और 2006 में बर्दवान दक्षिण सीट से विधानसभा चुनाव जीता था. लेकिन 2011 में वह तृणमूल कांग्रेस से हार गए थे.

उत्तर भारत में ठंड की मार, कोहरे से दिल्ली में दमघोंटू हुई हवा

नई दिल्ली (आरएनएस)। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लोग कड़ाके की ठंड से रविवार को सर्दी ने पिछले 12 साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया, वहीं सोमवार को भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं थी। स्काईमेट के मुताबिक अगले 48 घंटे तक लोगों को सर्दी से मामूली राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद पारा फिर तेजी से नीचे गिरेगा। उसके बाद सप्ताह के अंत तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सुबह से ही सड़कों पर कोहरे की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई। वहीं सफदरजंग में पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत की बात करें तो सोमवार को पंजाब के अमृतसर में सबसे कम 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

भारत जैसा सहिष्णु कोई दूसरा मुल्क नहीं: राजनाथ

नई दिल्ली(आरएनएस)। देश में असहिष्णुता को लेकर फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बयान के बारे में जारी बहस के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि हिन्दुस्तान जितनी सहिष्णुता दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं है। सिंह ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के 114वें स्थापना दिवस समारोह से इतर संवाददाताओं से बातचीत में अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के हाल के बयान के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, कि भारत में जितनी सहिष्णुता है, वह समझते हैं कि दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी।

मनमोहन राज में हर माह टैप होते थे 9 हजार फोन!

नई दिल्ली(आरएनएस)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने एक आरटीआई का हवाला देते हुए दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के राज में हर माह 9 हजार फेन और 500 ईमेल टैप होते थे। इस आरटीआई के अनुसार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के कार्यकाल के दौरान 2013 में सरकारी एजेंसियों को कानूनी तौर पर निगरानी करने के लिए अधिकार दिए गए थे।

भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को 7 साल की सजा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के शेष दो मामलों में उन्हें दोषी करार दिया। इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत ने 68 वर्षीय शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल मामलों में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई। शरीफ पर 2.5 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया। शरीफ फिलहाल भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले पहले से ही में जेल में हैं। द डॉन के अनुसार, फैसला सुनने के लिए नवाज शरीफ अदालत में मौजूद थे। जज अरशद मलिक ने नवाज के कोर्ट रूम में पहुंचने के कुछ ही मिनटों में अपना संक्षिप्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, फ्लैगशिप इनवेस्टमेंट मामले में आरोपी के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। अल अजीजिया स्टील मिल केस में दोष सिद्ध होता है।

राजनीतिक वनवास झेल रहे नवाज शरीफ के समर्थक बड़ी संख्या में कोर्ट रूम के बाहर मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शरीफ समय पर अदालत पहुंच गए थे और इस दौरान वह बिल्कुल शांत नजर आ रहे थे। हालांकि, शरीफ के पास इस फैसले को चुनौती देने का विकल्प मौजूद है।

बता दें कि इन दोनों मामलों पर पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी कर लेने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। नवाज शरीफ पर इससे पहले भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लग चुके हैं। उन्हें 10 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किया जा चुका है। पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे शरीफ के कुनबे के लिए यह फैसला बड़ा झटका है। बता दें कि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने चुनाव प्रचार में शरीफ परिवार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था।

नए वर्ष में आएंगे दस लाख नए रोजगार

दस फीसदी तक बढ़ सकता है वेतन

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रौद्योगिकी में बदलाव से इस साल कई पारंपरिक नौकरियों की जगह नई नौकरियों ने ले ली, वहीं वेतन में करीब 8-10 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई। दूसरी ओर अगर आने वाले साल की बात करें तो विशेषज्ञों एवं नियोक्ताओं को लगता है कि नए वर्ष में करीब 10 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वेतनवृद्धि पिछले साल की तरह ही बनी रह सकती है, हालांकि कुछ खास क्षेत्र के लोगों की वेतन में अधिक बढ़ोतरी भी हो सकती है। अगले साल होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर संभावना जताई है जा रही है कि राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए नियोक्ता 2019 की पहली छमाही में सतर्क रुख अख्तियार कर सकते हैं। रोजगार सृजन हाल के समय में बहस का बड़ा अहम मुद्दा रहा है, क्योंकि तेज व्यापक आर्थिक वृद्धि के बावजूद रोजगार सृजन की गति उम्मीद के अनुरूप नहीं रही है, दूसरी ओर एक आकलन के मुताबिक हर साल 1.2 करोड़ लोग रोजगार बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है

कि देश में रोजगार सृजन को लेकर पर्याप्त और विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव के कारण भी स्थिति ज्यादा बदतर हो गई है। साल 2016 के नवंबर में नोटबंदी और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किए जाने के बाद 2018 में भारतीय रोजगार बाजार फिर से पटरी पर लौटता नजर आया। सोसायटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट (एसएचआरएम) के परामर्श विभाग के प्रमुख निशिथ उपाध्याय के मुताबिक, यह विडंबना है कि आम चुनाव के दौरान रोजगार सृजन एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, इसके बावजूद संगठन 2019 में अपनी कारोबारी योजना को लागू करने को लेकर सतर्कता का रुख अपना सकते हैं।

अटल पर 100 का सिक्का जारी करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर आज सोमवार को उनकी स्मृति में सौ रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक संसद भवन के एनेक्सी में एक कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री महेश शर्मा की मौजूदगी में मोदी यह सिक्का जारी करेंगे। इस सिक्के का वजन 35 ग्राम और त्रिज्या 2.2 सेंटीमीटर होगी। यह 50 पचास प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, पांच प्रतिशत निकेल और पांच प्रतिशत जस्ते का बना होगा। इस सिक्के के अग्रभाग पर बीच में अशोक स्तम्भ होगा जिसके नीचे 'सत्यमेव जयते' लिखा होगा। वृत्त पर बायीं ओर भारत और दाहिनी ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। अशोक स्तम्भ के नीचे रुपए का प्रतीक चिह्न और अंग्रेजी के अंक में 100 लिखा होगा। सिक्के के पीछे की तरफ वाजपेयी का चित्र होगा। ऊपर के वृत्त पर बायीं ओर देवनागरी में और दाहिनी ओर अंग्रेजी में अटल बिहारी वाजपेयी लिखा होगा। वृत्त के निचले हिस्से में अंग्रेजी के अंकों में 1924 और 2018 लिखा होगा। उल्लेखनीय है कि वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और इस वर्ष 16 अगस्त को उनका निधन हो गया था।

कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में असंतोष

सरकार से बाहर हुए मंत्री ने दी पार्टी छोड़ने की धमकी

बेंगलुरु। कर्नाटक के एचडी कुमारस्वामी सरकार के कैबिनेट विस्तार के तहत शनिवार को मंत्रिमंडल में आठ नए मंत्री शामिल हुए। वहीं दो मंत्रियों कांग्रेस के रमेश जारकिहोली (नगर प्रशासन) और निर्दलीय विधायक आर शंकर (वन एवं पर्यावरण) को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। उधर, मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने के बाद अब जारकिहोली ने पार्टी छोड़ देने की धमकी दी है। साथ ही पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी सहित कई कांग्रेसी विधायक कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाखुश हैं।

रामलिंगा रेड्डी के समर्थकों ने सोमवार को इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता सदानंद गौड़ा ने कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के विद्रोहियों का स्वागत करेगी। ऐसे में बीजेपी की इस सियासी पहल से कर्नाटक का राजनीतिक पारा गरमा गया है।

कैबिनेट से बाहर किए जाने पर एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में जारकिहोली ने कहा कि वह किसी भी समय विधायक के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या और कांग्रेसी विधायक भी उनके साथ हैं, रमेश ने कहा, मैं अभी संख्या नहीं बताऊंगा। एक सप्ताह इंतजार कीजिए। उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा, मैं पिछले तीन महीने से इसके लिए (इस्तीफा) सोच रहा था। मेरा अगला कदम क्षेत्र और राज्य की जनता के हित में होगा। सूत्रों के मुताबिक श्रीमंत पाटिल सहित कांग्रेस के एक और विधायक और एमलएसी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले बेंगलुरु में पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर पर उन्हें कैबिनेट से दूर रखने का आरोप लगा चुके हैं। बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को अपने छह महीने पुराने कैबिनेट का विस्तार करते हुए इसमें गठबंधन साझेदार कांग्रेस के आठ सदस्यों को शामिल किया। नए मंत्रियों में सतीश जारकिहोली, एमबी पाटिल, सीएस शिवल्ली, एमटीबी नागराज, ई तुकाराम, पीटी परमेश्वर नाइक, रहीम खान और आरबी थिम्मारपुर शामिल हैं।

गहलोत सरकार में सिर्फ 1 महिला मंत्री, वसुंधरा राजे कैबिनेट में थीं चार

जयपुर। राजस्थान में सोमवार को कैबिनेट का गठन हो गया है। गहलोत सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के तहत 23 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इसमें 13 कैबिनेट जबकि 10 राज्यमंत्री शामिल हैं। हालांकि राजस्थान के कैबिनेट विस्तार में इस बार महिलाओं को नजरअंदाज किया गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 23 मंत्रियों में से सिर्फ एक महिला विधायक ममता भूपेश ने ही मंत्री पद की शपथ ली है। इसकी तुलना में पिछली बार वसुंधरा राजे के मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री थीं। सोमवार को राजस्थान में हुए कैबिनेट विस्तार में ममता भूपेश ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली है। वह सिकराय निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं। बात करें पूर्व की वसुंधरा राजे सरकार की तो उनके कैबिनेट में 4 महिला मंत्री थीं जिनमें से एक

राज्यमंत्री के पद पर थीं। इनमें महिला एवं बाल विकास मंत्री के पद पर अनीता भदेल, शिक्षा मंत्री के रूप में किरण माहेश्वरी और पर्यटन मंत्री कृष्णेंद्र कौर (दीपा) शामिल थीं। वहां वसुंधरा के मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री कमसा मेघवाल दलित चेहरे में रूप में शामिल थीं। दिलचस्प यह है कि इस बार राजस्थान चुनाव में कुल 179 महिला उम्मीदवार थीं जिनमें से 23 महिलाएं विधायक चुनी गई थीं। हालांकि इस मामले में राजस्थान का अपना इतिहास रहा है जिसमें महिला विधायकों की संख्या में भी गिरावट आई है। जहां 2008 में 28 महिला विधायक चुनी गई थीं, वहीं 2013 में 25 विधायक चुनकर आई थीं।

हाइवे पर 50 गाड़ियां टकराईं, 7 लोगों की मौत

झज्जर (आरएनएस)। हरियाणा के झज्जर में कोहरे के कारण रोहतक-रेवाड़ी हाइवे पर करीब पचास गाड़ियां आपस में टकरा गई. इस घटना में सात लोगों की मौत हो गई और दर्जनभर घायल हुए हैं. मृतकों में 6 महिलाएं हैं. जानकारी के अनुसार, झज्जर के बादली फ्लाईओवर पर दो गाड़ियां टकरा गई. इसके बाद पीछे से आ रही स्कूल बस, कार और कई बड़ी गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गई. इस घटना के बाद हाइवे पर करीब दो किलोमीटर लंबा जाम लग गया.

बंगाल में रथयात्रा पर रोक के हाईकोर्ट के फैसले को भाजपा ने सुको में दी चुनौती

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल यूनिट ने राज्य में पार्टी की रथयात्रा रोकने की कलकत्ता हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के फैसले को चुनौती दी है। शनिवार को हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सिंगल बेंच के फैसले को खारिज कर दिया था। इस फैसले में भाजपा को रथयात्रा निकालने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देबाशीष कारगुप्ता और जस्टिस शंपा सरकार की डिविजन बेंच ने केस को वापस सिंगल बेंच को भेजते हुए कहा था कि वह राज्य सरकार की एजेंसियों के इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करे।

ज्ञात हो कि बीजेपी द्वारा पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित रथयात्रा को कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को मंजूरी दी थी। एकल पीठ के इस आदेश को पश्चिम बंगाल सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को 7 दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी। फैसले के खिलाफ अपील के लिए मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाते हुए राज्य सरकार ने इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। राज्य सरकार के तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल ने यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उस आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति तापब्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने गुरुवार को बीजेपी के रथयात्रा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले, 6 दिसंबर को एकल पीठ ने भी रथयात्रा को मंजूरी नहीं दी थी।

सेना के अधिकारी को बर्खास्त करने की सिफारिश

नई दिल्ली (आरएनएस)। आर्मी जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने रविवार को सेना के एक मेजर जनरल को दो साल पुराने यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की है। जीसीएम की अध्यक्षता करते हुए ले.जनरल रैंक के अधिकारी ने तड़के सुबह साढ़े तीन बजे आरोपी अधिकारी को आईपीसी सेक्शन 354 अ और आर्मी एक्ट 45 के तहत दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया। सेना के अधिकारी ने बताया कि मेजर जेनरल के

खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत मुकदमा चल रहा था मगर कोर्ट ने उन्हें सेक्शन 354 अ के तहत भी दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया। दोषी अधिकारी के वकील आनंद कुमार ने कहा कि जीसीएम ने डिफेंस के केस को प्राथमिकता नहीं दी और अब वह कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करेंगे।

रिहाई के 21 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने पलटा फैसला

0-रेप मामले में दोषी को दी सजा

मुंबई (आरएनएस)। इक्कीस साल पहले नासिक के रहने वाले एक शख्स पर 11 वर्षीय लड़की से रेप करने का आरोप लगा था। यही नहीं, आरोपी को उस दौरान बरी भी कर दिया गया था। हालांकि, 21 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले पर ऐक्शन लेते हुए शनिवार को उसे दोषी करार दिया है। जस्टिस इंद्रजीत महंती और विश्वास जाधव की खंडपीठ ने वर्ष 1997 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मछिंद्र सोनवाने (जो घटना के वक्त 19 वर्ष का था और अब उम्र 41 वर्ष है) को रिहा करने के फैसले पलटते हुए उसे रेप के मामले दोषी पाया और सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। दो दशकों की देरी होने पर आरोपी के ऊपर दया बरतने संबंधी याचिका को बेंच ने खारिज कर दिया और सोनवाने को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को 1 लाख रुपये बतौर मुआवजा दे। सोनवाने को सरेंडर करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में सेशन कोर्ट ने गलती करते हुए लापरवाही भरा रवैया अपनाया है। सत्र न्यायालय द्वारा एक एक्सरे रिपोर्ट को आधार मानकर आरोपी को बरी कर दिया गया था, जिसमें पीड़िता की उम्र 14 वर्ष दिखाई गई है। दो से तीन साल के अंतराल की गलती को ध्यान में रखकर पीड़िता की उम्र को 16 वर्ष निर्धारित किया गया, जो कि उस वक्त सहमति की आयु थी।